>

Title: Need to continue the Technology Upgradation Fund Scheme in the interest of cotton thread mills and farmers in Maharashtra.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने नई वस्त्र नीति घोषित की है। महाराष्ट्र देश के कपास का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है, मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास को कैश क्रॉप माना जाता है। यहां के किसानों की सारी अर्थव्यवस्था कपास से जुड़ी हुई है। किंतु उत्पादित कपास में केवल 20 प्रतिशत कपास ही राज्य में प्रक्रिया होती है, बची हुई 80 प्रतिशत कपास दूसरे राज्यों में भेजी जाती है या अन्य देशों में निर्यात की जाती है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष नई वस्त्र नीति घोषित की है। इस नीति में राज्य की सभी वस्त्रोद्योग इकाई को ज़ीरो प्रतिशत ब्याज पर राशि उपलब्ध की जाएगी और नए वस्त्रोद्योग लगाने के लिए दस प्रतिशत भाग भांडवल दिया जाएगा जिसका उद्योग जगत ने भी स्वागत किया है। किंतु यह नीति केन्द्र सरकार के टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड से जुड़ी हुई है। मुझे महाराष्ट्र सरकार से ऐसी सूचना मिली है कि केन्द्र सरकार टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को अगले वर्ष से बंद करने जा रही है। मेरा मानना है कि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड के अंतर्गत सूत धागा मिलों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करना वस्त्रोद्योग और किसानों के हित में नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो नई वस्त्र नीति घोषित की है उसका महत्व भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं चल रही सूती धागा मिलों को भी टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड न होने के कारण अपना अपग्रेडेशन करना संभव नहीं होगा और किसानों को कपास का उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा। सन् 2010 में टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड की समीक्षा के लिए सीआरआईएसआईएल समिति बनाई गई थी। सीआरआईएसआईएल समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को बंद नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को चालू रखने की केन्द्र सरकार को सिफारिश की है, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सर्वप्रथम सूत धागा मिलों और किसानों के हित की रक्षा करे और टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को बंद न करे।